

छात्राओं की साइकिल खरीद पर घमासान

‘आप’ ने लगाया 90 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जा रही साइकिलों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने साइकिल खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए रेखा गुप्ता सरकार पर करीब 90 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने जिस मॉडल की साइकिल खरीदने का दावा किया, वास्तव में छात्राओं को उससे अलग और कम कीमत वाला मॉडल वितरित किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सी.बी. सोरभ भारद्वाज ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार द्वारा जारी वर्क ऑर्डर में स्पष्ट रूप से हीरो स्काइलर 26टी मॉडल की साइकिल खरीदने का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार, यह मॉडल कई वर्षों पहले बाजार में उपलब्ध था, लेकिन कंपनी ने इसका उत्पादन काफी पहले बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्राओं को जो साइकिलें दी जा रही हैं, वे वास्तव में हीरो बोनफायर मॉडल हैं, जिन पर केवल साइकिल का स्टीकर लगाकर उन्हें दूसरे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सोरभ भारद्वाज ने दावा किया कि स्काइलर मॉडल में सात गियर, डिस्क

ब्रेक और फ्रंट सर्पेसेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जबकि वितरित की जा रही साइकिलों में इनमें से कोई भी सुविधा भीजुद नहीं है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने स्काइलर मॉडल के नाम पर किसी अन्य मॉडल की साइकिल खरीदी है, तो यह केवल कीमत का अंतर नहीं बल्कि मॉडल के स्तर पर भी गंभीर अनियमितता का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार वास्तविक मॉडल की जानकारी देने से बच रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संबंधित विभाग के मंत्री से कई बार सार्वजनिक रूप से यह पूछा गया कि छात्राओं को किस



मॉडल को साइकिल वितरित की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हीरो साइकिल के डीलरों और थोक विक्रेताओं से मिली जानकारी के अनुसार स्काइलर मॉडल का निर्माण काफी पहले बंद हो चुका है। 'आप' का आरोप है कि हीरो बोनफायर मॉडल की थोक कीमत चार हजार रुपये से भी कम है, जबकि सरकार ने प्रत्येक साइकिल की खरीद पर लगभग 6,957 रुपये का भुगतान किया है। पार्टी का कहना है कि करीब 1 लाख 30 हजार साइकिलों की खरीद में प्रति साइकिल लगभग 3 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च किए

गाए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसी आधार पर पार्टी ने पूरे मामले को लगभग 90 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जोड़ते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीर्री भादवा ने कहा कि यदि सरकार के दावे सही हैं तो उसे खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। उन्होंने टैंडर प्रक्रिया, मॉडल चयन, कंपनी के साथ हुए अनुबंध, श्रुतान्त संबंधी रिपोर्ट और तकनीकी स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता को यह पता लग सकेगा कि छात्राओं के लिए किस मॉडल की साईकल खरीदी गई है और आदमी पार्टी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद छात्राओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दीयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ललिताल यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। सरकार को ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या खंडन अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई जांच और सरकारी पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

नई दिल्ली (एजेंसी) । देश की औपधिविनियामक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औपधिनियम, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए प्रावधानों तहत अब यदि कोई संस्था या आवेदक औपधियों से संबंधित लाइसेंस या अन्य स्वीकृतियों के लिए आवेदन करते समय फर्जी, मगनगढ़ या भ्रामक आंकड़े एवं दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसके खिलाफ केवल आवेदन निरस्त करने या लाइसेंस रद्द करने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे निर्धारित अवधि तक नया आवेदन करने से भी रोक जा सकेगा। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन 16 अक्टूबर, 2025 को जीएसआर संख्या 756 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह प्रावधान औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत लागू होगा और औपधिनियम, 1945 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर किए जाने वाले सभी प्रकार के आवेदनों पर समान रूप से लागू रहेगा। संशोधित नियमों के तहत राज्य और केंद्र स्तर के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि जहां में यह पाया जाता है कि किसी संस्था ने आवेदन के समर्थन में फर्जी, भ्रामक या मगनगढ़ वैज्ञानिक आंकड़े अथवा दस्तावेज



**MINISTRY OF
HEALTH AND FAMILY
WELFARE**

प्रस्तुत किए हैं, तो संबंधित प्राधिकरण उस संस्था के भविष्य के आवेदन निर्धारित समय तक स्वीकार नहीं करेगा। इससे औषधि स्वीकृति प्रक्रिया में थोखा थड़ी करने वाले संस्थानों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्था के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। संबंधित संस्था को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि संस्था कार्रवाई से असंतुष्ट होती है, तो उसके लिए अपील करने का भी प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्राभावकारिता का मूल्यांकन पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रमाणीत आंकड़ों पर आधारित होता है। यदि कोई संस्था गलत या मगनदंत आंकड़े प्रस्तुत करती है, तो इससे न

केवल नियामक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि मरीजों तक पहुँचने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर भी गंभीर असराल खड़े हो सकते हैं। ऐसे स्थिति जिनमें स्वास्थ्य के लिए बढ़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार यह संशोधन ऐसे कदाचार को रोकने, आवेदकों की जवाबदेही बढ़ा और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि देश में केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर ही औषधियों को मंजूरी मिले। सरकार कहना है कि यह कदम भारत की औषधि विनियामक प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुसार मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे नियमों का पालन करने वाले औषधि निर्माता और वितरक को प्रोत्साहित होगा, जबकि अनियमितता और फर्जीवाड़ा करने वाली संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

पंजाब खेल में पिछड़ रहा, दूसरे राज्य बढ़ रहे : हरभजन सिंह

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर और राज्य सभा सांसद हरभजन सिंह ने गुरुवार को कहा कि पंजाब खेल के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है, जबकि दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे हैं। हरभजन सिंह ने संसद परिसर में आईएसएसएस से कहा, 'खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं समझता हूं क्योंकि मैंने खेला है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब के खेल से जुड़ी संसदाओं को बेतहाशा बनाने के लिए काम किया जाएगा। मैं सालों से कह रहा हूं कि पंजाब खेल के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है, जबकि दूसरे राज्य आगे बढ़ गए हैं। वे राज्य भी भारत का हिस्सा हैं, लेकिन एक पंजाबी होने के नाते, मुझे लगता है कि पंजाब, जो कभी खेल में सबसे आगे था, अब मुख्य रूप से संसाधन और संरचना की कमी और बहुत से युवाओं के विदेश चले जाने की वजह से पिछड़ गया है।' उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के युवाओं पर ध्यान दिया जाए, उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो राज्य देश की बेहतरिनी खेलीट दे सकता है और फिर से देश में खेलों के मामले में शीर्ष राज्य बन सकता है।

दलमा में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम

सारयकेला । झारखंड के दलमा जंगल क्षेत्र में माओवादियों की नई गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सारयकेला-खुसवा के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्णिगारी ने गुवागार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद माओवादी संगठन दलमा इलाके में फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। संयुक्त अभियान चलाकर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस दौरान तीन इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी निशानदेही पर दलमा पहड़ाई क्षेत्र में एक गांव की जखीरा भी बरामद किया गया है। बरामद सामान में पुलिस बल से लूटी गई इंसास, एकेएम-47 की बड़ी संख्या में जिंदा गोलीयां, 9 एमएम पिस्तौल, मैगजीन, बॉकी-टॉर्च, कोडेक्स वायर, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री शामिल है। एस्परी ने बताया कि चार आगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि कांडा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य छिपे हुए हैं। इसके बाद जिला पुलिस, 2013 कोबरग, एसआरपीएफ की 134वीं बटालियन और एसआरपीएफ 26वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।

राष्ट्रीय विस्तार की तैयारी में सीजेपी, पहली कार्यकारिणी घोषित

छत्रपति संभाजीनगर(एजेंसी)। कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के नामों का औपचारिक ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि नए नेतृत्व के माध्यम से संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा और अगले छह महीनों में देशभर में संगठनात्मक विस्तार का अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 वर्षीय अभिजीत दिपके को संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं आशुतोष रांका और सौरव दास को राष्ट्रीय सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए अजिंक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन



प्रभारी तथा दीपक बलियान को संगठन सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आफरीन नवाज को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी ने विभिन्न विभागों के लिए भी पदाधिकारियों की घोषणा की है। रिजत रेड्डी मल्लांगी को मीडिया प्रमुख, रत्ना सिंह को विधिक मामलों की प्रमुख, वैष्णवी गौर को अनुसंधान एवं नीति प्रमुख,



रोहन देशपांडे को प्रौद्योगिकी प्रमुख तथा योगेश इंगले को वित्त प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के क्षेत्रीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए चार जोनल प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। उत्तर क्षेत्र का प्रभार दीपक बलियान, दक्षिण क्षेत्र का विजय रेड्डी मल्लांगी, पूर्व एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र का अंकित भारद्वाज तथा पश्चिम क्षेत्र का दायित्व

नाराज कर्नाटक विधान परिषद अध्यक्ष होस्टी 14 अगस्त को पद से इस्तीफा देंगे

बेंगलुरु (एजेंसी) बेंगलुरु कर्नाटक विधान परिषद अध्यक्ष बक्सराज होरट्टी ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि वे 14 अगस्त को आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने नए मंत्रियों की सूची जारी करते हुए वरिष्ठ नेता सलीम अहमद का नाम इस पद के लिए घोषित किया है। इस कदम से विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आलोचना करते हुए कहा है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए उम्मीदवार का नाम घोषित करना परंपरा के विरुद्ध है। पार्टी का कहना है कि अध्यक्ष पद संवैधानिक



रूप से पवित्र है और इसे पार्टी की राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। इस बीच, केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने गुरुवार को कर्नाटक विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और विचार-विमर्श किया।

गोवर्धन परियोजना देश की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है : पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अखंड रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23,73,731 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली राष्ट्रीय चक्रवर्ती जेब ऊर्जा योजना, गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी भी साझा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम! उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे संपीड़ित बायोगैस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। यह योजना निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी। इससे हमारे किसानों, सहकारी समितियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को

A portrait of Narendra Modi, the Prime Minister of India, wearing a white kurta and a grey vest, with the Indian flag in the background.

लाभ होगा, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, आयतिष्ठत जीवाश्म ईधन पर निर्भरता कम होगी और वैज्ञानिक अधशिक्षण प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। गोविधन परिधोजना देश की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों, गोबर, प्रेस मड (गन्ने की 'मैली'), नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य जैव-द्रव्यमान संसाधनों को स्वच्छ ईधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आय का मूल्य में परिवर्तित करेगी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से

वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू की जाएगी और संपीड़ित बायोगैस को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख आधार स्थापित करेगी। सुनिश्चित मांग, लाभकारी और स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पापेपलान अवसरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से, गोधनदेश बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक मजबूत और पूर्वामांनित ढांचा प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य घरेलू संपीड़ित बायोगैससुत (सीबीजी) उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और पूरे देश में एक जीवंत चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था निर्माण करना है। पिछले कई वर्षों में, सरकार ने सतत वैकल्पिक किरायादी परिवहन (सतत) पहल, जैविक खाद के लिए बाजार विकास

सहायता (एमडीए) योजना, बायोमास एकोनोकरण मशीनी (बीएएम) योजना, पाइपलाइन अवसंरचना विकास (डीपीआई) योजना और राष्ट्रीय उर्वर उर्जा कार्यक्रम के तहत संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र की नींव को व्यवस्थित रूप से मजबूत किया है। इन सभी पहलों के समूहीकृत प्रयास से 200 से अधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना संभव हो पाई है, उत्पादन और निर्यात प्रणालियां स्थापित हुई हैं, जैविक खाद मूल्य श्रृंखला मजबूत हुई है और विभिन्न फोडस्टक और भौगोलिक क्षेत्रों में सीबीजी की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। अब गोवर्धन इस प्रगति को अगले स्तर पर ले जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रशंसित यह योजना संपूर्ण सीबीजी मूल्य श्रृंखला में एक एकीकृत मंच तैयार करती है।

हरियाणा: चरखी दादरी में पुलिस स्टेशन के बाहर गैंगवार, सात लोग घायल

चरखी दादरी(एन्सें)। हरियाणा के चरखी दादरी शहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुस्वार को पुलिस स्टेशन के सामने दिनदहाड़े अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें एक कार में सवार सात लोग घायल हो गए। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह अपराध गैंगवार से जुड़ा है। हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जिन्होंने कम से कम 30 राउंड फायरिंग की थी। यहां चौकाने वाली बात यह है कि गोलीबारी के बाद तीन हमलावर रिवांल्वर लहराते हुए पैसूल भी भाग गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल लोग गोमियों से छलनी एसयूवी कार में बैठे दिख रहे हैं। घायलों को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं, अपराध की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फायरिंग



इतनी अचानक हुई कि राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के दौरान गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए चरखी दादरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद, सभी सात घायलों को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान चरखी दादरी के अंकित, हिमार के कीर्तिमान, भिवानी के सूरज और अंकित, हिमार के सनी, महेंद्रगढ़ के कृष्ण और फतेहगढ़ के अमित के तौर पर हुई है।

बिजली व्यवस्था में लापरवाही पर सख्त हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि जनता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में जले हुए ट्रांसफार्मरों के समय पर प्रतिस्थापन, शिकायतों के निस्तारण, कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत सुरक्षा तथा प्रदेश की समग्र बिजली व्यवस्था की समीक्षा की गई। मंत्री ने देवरिया, गाजीपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर समेत कई जनपदों में जले ट्रांसफार्मरों को समय पर न बदले जाने और बिजली आपूर्ति



संबंधी शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता को अनावश्यक परेशानी पहुंचाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही हर हाल में तय की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंताओं से जवाब-तलब करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक में गाजीपुर जिले के गहमर क्षेत्र में 12 दिनों से जला ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर

संबंधित अधिशासी अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं संबंधित अधीक्षण अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराए जाने पर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से जले ट्रांसफार्मर को न बदले जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मुख्य अभियंता, गोरखपुर (द्वितीय) को प्रतिवृत्त (एडवर्स एट्टी) देने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली संबंधी शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी और गंभीरता से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से

किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कांवड़ मार्गों पर विद्युत सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। ढीले बिजली के तार, झुके हुए खंभे, खुले विद्युत उपकरण तथा अन्य संभावित खतरों को तत्काल दूर किया जाए। साथ ही यात्रा मार्गों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने और लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार, मयूर माहेश्वरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारी वचुंअल माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

कांग्रेस कार्यालय 15 दिन में खाली करने का आदेश नजूल भूमि पर अवैध कब्जा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। जनपद सीतापुर में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को लेकर नगर पालिका परिषद ने बड़ा प्रशासनिक फैसला सुनाया है। तामसेनगंज स्थित ऐतिहासिक घंटाघर भवन की पहली मंजिल पर संचालित कांग्रेस कार्यालय को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी एवं न्यायिक उपजिलाधिकारी सीमा सिंह ने कांग्रेस कमेटी की ओर से दाखिल आपत्तियों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और भवन का कब्जा नगर पालिका को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर परिसर खाली नहीं किया गया तो प्रशासन बलपूर्वक कब्जा लेगा। इसके लिए होने वाली पूरी कार्रवाई का खर्च भी संबंधित पक्ष से ही वसूला जाएगा। मामले की शुरुआत जिलाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारी वचुंअल माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए।



पर कांग्रेस कार्यालय संचालित मिलता पाया गया इसके बाद जिलाधिकारी ने नजूल मैनुअल के नियम-74 के तहत कार्रवाई के कब्जे में है और तत्कालीन सरकार द्वारा उन्हें 1972 से किरायेदारी का दावा, लेकिन नहीं मिले दस्तावेज सुनवाई के दौरान कांग्रेस कमेटी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा किया कि वर्ष 1972 से भवन उनके कब्जे में है और तत्कालीन सरकार द्वारा उन्हें यह परिसर आवंटित किया गया था। हालांकि नगर पालिका की जांच में इस दावे के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार कांग्रेस ने इस भवन का अंतिम किराया 6 फरवरी 1971 को 320 रुपये जमा किया था। इसके बाद करीब 55 वर्षों तक कोई किराया जमा नहीं किया गया जांच

के दौरान कांग्रेस की ओर से न तो कोई वैध पट्टा, लीज डीड और न ही कोई इकरारनामा प्रस्तुत किया जा सका। इन्हीं तथ्यों के आधार पर नगर पालिका ने कांग्रेस को डिफॉल्टर मानते हुए भवन पर कब्जे को अवैध घोषित कर दिया नगर पालिका ने अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि नजूल भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहता है सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा हस्तांतरण या उपयोग वैध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कांग्रेस कमेटी की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए भवन खाली कराने का आदेश पारित किया गया। 15 दिन बाद होगी बलपूर्वक कार्रवाई आदेश में कहा गया है कि कांग्रेस कमेटी को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से भवन खाली कर नगर पालिका को कब्जा सौंपना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन पुलिस बल की मौजूदगी में परिसर खाली कराएगा। इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूल जाएगा!!

गोमती नगर रेलवे स्टेशन आवांटियों का आरएलडीए के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से जुड़ी आर1 - आर2 कर्मशियल कॉम्प्लेक्स व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) पर परियोजना में अत्यधिक विलंब का आरोप लगाते हुए आवांटियों की समस्याओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है।



एसोसिएशन का कहना है कि वर्ष 2020-21 में निर्माण आधारित भुगतान योजना के तहत आवंटित इस प्रीमियम वाणिज्यिक परियोजना में अधिकांश आवंटी लगभग 95 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं, लेकिन निर्धारित समय के बावजूद अब तक न तो निर्माण पूरा हुआ है और न ही दुकानों का कब्जा दिया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि परियोजना का कब्जा 30 सितंबर 2023 तक दिया जाना था, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई। इस देरी के कारण कई आवंटी बैंक ऋण, ईएमआई, किराया और अन्य वित्तीय दायित्वों के बोझ तले दब

गए हैं। कई लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी इस परियोजना में निवेश की थी, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि शिकायतों के समाधान के लिए नई दिल्ली स्थित परियोजना कार्यालय से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले। मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाया गया, जहां निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए, फिर भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि लगातार तनाव के कारण कुछ आवंटी

जांच में दोषी पाए जाने पर मिले कड़ी से कड़ी सजा : ज्ञान तिवारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/सीतापुर। महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में महिलाओं से कथित रूप से शादी कर ठगी करने के आरोपों में गिरफ्तार अनूज त्रिवेदी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच सेवता विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उनके साथ उनकी पुत्री डॉ. प्रज्ञा तिवारी भी मौजूद रहीं। लाइव प्रसारण के दौरान विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि इस विषय पर वह किसी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी और पीड़ित पिता के रूप में अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में अनूज त्रिवेदी के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित होते हैं तो उसे कानून के तहत सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी बेटी अब हमेशा अपने मायके में ही रहेगी। ज्ञान तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी बेटी डॉ. प्रज्ञा तिवारी का विवाह मिश्रिख निवासी प्रखर त्रिवेदी के साथ पूरे सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार कराया था। प्रखर, अनूज त्रिवेदी



का पुत्र है। विधायक के अनुसार विवाह के समय उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके समधी पर अलग-अलग राज्यों में महिलाओं से कथित धोखाधड़ी, फर्जी पहचान अपनाने और कई शादियां करने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक-एक कर अनूज त्रिवेदी से जुड़े मामले सामने आने लगे तो पूरा परिवार हैरान रह गया। उन्हें लगा कि केवल उनकी बेटी ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार विश्वासघात का शिकार हुआ है।

जांच निष्पक्ष हो, किसी को न मिले संरक्षण

विधायक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग पहचान बनाकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करता है तो यह अत्यंत

गंभीर अपराध है। जांच एजेंसियां यदि आरोपों की पुष्टि करती हैं तो आरोपी को कानून के अनुसार कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बचाने की कोशिश

कर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, उसी परिवार से इतना बड़ा धोखा मिलने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटी को न्याय दिलाना और उसका भविष्य सुरक्षित करना है।

कई राज्यों में दर्ज हैं मुकदमे
अनूज त्रिवेदी के खिलाफ महाराष्ट्र, प्रयागराज सहित कई राज्यों में महिलाओं से कथित तौर पर शादी कर ठगी करने, फर्जी पहचान अपनाने और अन्य आरोपों में मुकदमे दर्ज बनावे जा रहे हैं। कई महिलाएं भी सामने आकर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है।

अंत में विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि उनका परिवार जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देगा। उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल उनके परिवार का मामला नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के न्याय का प्रश्न है, जो कथित रूप से इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं।

महमूदाबाद में परंपरागत जुलूस-ए-अरबाइन अक्रीदत और गमगीन माहौल में संपन्न

महमूदाबाद-सीतापुर।

आज के दिन 6 अगस्त को कर्बला के शहीदों की याद में परंपरागत जुलूस-ए-चेहल्लुम वक्फ महाराजा साहब के तत्वोवाधन में मुवल्ली प्रोफेसर अली खान साहब (राजा महमूदाबाद) के नेतृत्व में दोपहर को किला महमूदाबाद से बरामद हुआ। इस जुलूस में



ऊँट, दुलदुल, अलम, ताबूत व ताजिजे शाही साज-सज्जा से सुसज्जित थे। जुलूस में सोजख्खानी व नौहाख्खानी अन्जुमन हेदरी, अन्जुमन सज्जादिया व अन्जुमन अब्वासिया कर रही थीं।अक्रीदतमद स्याह लिबास में जुलूस में शामिल रहे। सफर और समापन जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ अपराह्न 3 बजे अमीरांज स्थित कर्बला पहुंचा, जहाँ पर हजारों सोमावोरों ने गम के माहौल में सरो पर हसीन बलन्द किया और ताबूत व ताजिजे सुपुर्द-ए-खाक किये।

प्रशासन का सहयोग एवं धन्यवाद

स्थानीय पुलिस प्रशासन जुलूस को सम्पन्न कराने में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते रहे। इस जुलूस के समापन पर मुवल्ली वक्फ महाराजा साहब और तमाम गाजियादारों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।

महमूदाबाद में किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। महमूदाबाद क्षेत्र में यूरिया खाद की बढ़ती कीमतों, डीएपी की किल्लत और जटिल ई-केवाईसी व स्मार्टफोन आधारित प्रक्रियाओं के विरोध में किसानों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। पूर्व नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता के नेतृत्व में उनके आवास से लेकर तहसील मुख्यालय तक एक भव्य और रोषपूर्ण रैली निकाली गई।

हाथों में तिरंगा झंडे थामे और किसानों की एक ही मांग, यूरिया की आपूर्ति हो सुचारु, किसान कह रहे हो पूरा लिखी तखियां लेकर 'मोदी देउवा यूरिया दै देव भूखन मर जाब' के नारे लगाते हुए सैकड़ों किसान और ग्रामीण सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अमरीश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में किसानों को खेती के लिए जरूरी यूरिया और डीएपी समय पर नहीं मिल रही है, और जो मिल रही है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा, खेती-किसानी से जुड़ी ई-केवाईसी और स्मार्टफोन आधारित जटिल प्रक्रियाओं से ग्रामीण इलाकों के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए किसानों का यह जत्था तहसील पहुंचा, जहां प्रदर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री को सुचारु, किसान कह रहे हो पूरा लिखी तखियां लेकर 'मोदी देउवा यूरिया दै देव भूखन मर जाब' के नारे लगाते हुए सैकड़ों किसान और ग्रामीण सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारों से पूरा

बच्चों के भोजन में लापरवाही, दो पर दर्ज हुआ मुकदमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। महमूदाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय छंगपुर में मिड-डे मील (एमडीएम) की बद्दहाल व्यवस्था का मामला अब विभागीय कार्रवाई से आगे बढ़कर पुलिस तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर बच्चों को पानी जैसी सब्जी और जली हुई रोटियां परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पहले प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया, रसोइया की सेवा समाप्त की गई और अब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा मामला सोमवार को सामने आया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में बच्चों को बेहद पतली, पानी जैसी सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी जाती दिखीं। इतना ही नहीं, रोटियां बच्चों की थाली में रखने के बजाय फेंकी जा रही थीं। कुछ रोटियां जमीन पर गिरी सब्जी में गिरने के बाद भी उठकर बच्चों को परोस दी गईं। वीडियो में बच्चों को बेहद पतली, पानी जैसी सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी जाती दिखीं। इतना ही नहीं, रोटियां बच्चों की थाली में रखने के बजाय फेंकी जा रही थीं। कुछ रोटियां जमीन पर गिरी सब्जी में गिरने के बाद भी उठकर बच्चों को परोस दी गईं। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गोरखनाथ पटेल और एबीएसए की टीम

विद्यालय पहुंची। जांच के दौरान बच्चों ने भी वीडियो में दिख रही बातों की पुष्टि की और बताया कि उन्हें अक्सर खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जाता है। 63 बच्चों के स्कूल में मानकों की अनदेखी जांच में सामने आया कि विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक कुल 63 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। सोमवार के मेन्यू के अनुसार बच्चों को सब्जी और रोटी दी जानी थी, लेकिन उन्हें अत्यधिक पानी वाली आलू-तरोई की सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी गईं। अधिकारियों ने पाया कि भोजन तय मानकों के अनुसार नहीं बनाया गया था। दूध वितरण में भी अनियमितता मिली। बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैकवर्ड भोजन नहीं कराया जा रहा था, जो शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। ग्रामीणों की शिकायत और वायरल वीडियो ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। बीएसए की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने बुधवार को प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा को तत्काल पतली, पानी जैसी सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी जाती दिखीं। इतना ही नहीं, रोटियां बच्चों की थाली में रखने के बजाय फेंकी जा रही थीं। कुछ रोटियां जमीन पर गिरी सब्जी में गिरने के बाद भी उठकर बच्चों को परोस दी गईं। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गोरखनाथ पटेल और एबीएसए की टीम

वीडियो में बच्चों को बेहद पतली, पानी जैसी सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी जाती दिखीं। इतना ही नहीं, रोटियां बच्चों की थाली में रखने के बजाय फेंकी जा रही थीं। कुछ रोटियां जमीन पर गिरी सब्जी में गिरने के बाद भी उठकर बच्चों को परोस दी गईं। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।

में एफआईआर दर्ज करा दी गई। विभागीय जांच की जिम्मेदारी प्रथम विकासखंड के बीईओ पुष्पराज सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के भोजन से समझौता नहीं इस कार्रवाई को जिला प्रशासन ने कड़ा संदेश के तौर पर देखा है कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता से कोई छद्म नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मिड-डे मील योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। यदि कहीं भी लापरवाही या नियमों की अनदेखी मिलेगी तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वायरल वीडियो के बाद हुई इस कार्रवाई से जिले के अन्य सरकारी स्कूलों में भी मिड-डे मील व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। अब प्रशासन की नजर इस बात पर है कि बच्चों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो!!

बीडीओ ने प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर का किया औचक निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। आज ग्राम पंचायत जाफरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का खंड विकास अधिकारी सुमित सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना का गहन अवलोकन किया तथा बच्चों के साथ बैठकर स्वयं भोजन ग्रहण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वाद एवं स्वच्छता का निरीक्षण किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ने बच्चों से संवाद कर नियमित रूप से मिलने वाले भोजन, उसकी गुणवत्ता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों ने बताया कि



उन्हें प्रतिदिन स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय प्रबंधन एवं ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को नियत दिवस पर दूध एवं केला सहित

अन्य खाद्य सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। निरीक्षण के दौरान रसोइयों से भी उनके कार्य एवं मानदेय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। खंड विकास अधिकारी ने

विद्यालय परिसर की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय परिवार को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कृष्ण पाल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी सत्यार्थ वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष बृजेश वर्मा, प्रधानाध्यापक, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, रसोइयाएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सभी ने शांति की मंशा के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने एवं शिक्षा के साथ-साथ उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त किया।

गुमटी में चोरी का प्रयास करते पकड़ा गया चोर

महमूदाबाद-सीतापुर।

महमूदाबाद कस्बा क्षेत्र में देर रात एक परचून की गुमटी का ताला तोड़ते समय स्थानीय लोगों ने एक चोर को रो हाथों पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने महमूदाबाद निवासी आरोपी अखिलेश उर्फ नेता पुत्र पुतिलाल को हिरासत में लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 16 क्लिनिक प्लस शैंपू पाउच और ताला तोड़ने में इस्तेमाल की गई एक हथौड़ी बरामद हुई। पीड़ित दुकानदार की तटस्थी पर महमूदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद, सीतापुर। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र की सिरौली पुलिस चौकी अंतर्गत विश्वकर्मा पेट्रोलियम, भेथरा माधव के पास महमूदाबाद-सिधौली मुख्य मार्ग पर बुधवार को देर रात में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के महमदपुर मजरा तुरसेना गांव निवासी अनिल कुमार प्रताप सत्यवान अपनी मोटरसाइकिल (यूपी 32 सीई 3386) से किसी निजी कार्य से घर लौट रहे थे। इसी दौरान विश्वकर्मा पेट्रोलियम के पास तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अनिल कुमार



सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल सिरौली पुलिस चौकी और 108 एंबुलेंस सेवा को दी। सूचना मिलते ही सिरौली पुलिस चौकी प्रभारी फूल चंद्र सरोज तथा कांस्टेबल आशीष कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएसके) महमूदाबाद भिजवाया। सीएसके में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया।

जिंदगियां बचाने के लिए

हाल ही में लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े जो आंकड़े पेश किए गए थे विचलित करने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते साल सड़क दुर्घटनाओं में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान अप्रत्याशित रूप से हुए 5.13 लाख से अधिक सड़क हादसों में 1.83 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इन हादसों में घायल होने वालों का आंकड़ा किताब बड़ा होगा, निष्कर्ष निकालना कठिन न होगा। निश्चय ही यह बेहद चिंताजनक विरोधाभास है कि जिस देश में हर दिन सड़क हादसों में पांच सौ से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, वहां आधे से अधिक पंजीकृत मोटर वाहन बिना जरूरी बीमा के चल रहे हैं। हर बीता हुआ दिन 56 बताया जाता है। नागरिक स्तर पर तो यह एक अपराधिक लापरवाही है। यह, प्रोमन न कराने का स्तर मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने में बड़ी खामी को भी दर्शाता है। यह सुखद बात है कि न्यूमीन कोर्ट ने इन समस्या को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट आजमाने को कहा है, जिसके तहत वैध बीमा न होने वाले वाहन चालक को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया जा सकता है। बहुत संभव है इस योजना के क्रियान्वयन से बहुत सारे वाहन चालक वाहन बीमा कराने को बाध्य हो जाए। निश्चित रूप से थर्ड-पार्टी इश्योरेंस सिर्फ एक कानूनी जरूरत भर नहीं है। वास्तव में यह नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों को सालों तक अदालतों के चक्कर काटे बिना समय पर जरूरी मुआवजा मिल सके। यह सर्वविदित सत्य है कि जब लाखों गाड़ियां बिना बीमे के चलती हैं तो इन दुर्घटनाओं का बोझ हादसे के पीड़ितों और उनके परिवारों पर पड़ता है। जिसके चलते इनमें से कई लोग सड़क दुर्घटनाओं के शारीरिक और आर्थिक प्रभावों से उबरने के लिये संघर्ष करने रहते हैं। दरअसल, हाल ही में कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक सड़क दुर्घटना में स्थायी से रूप से विकलांग हुए एक बच्चे को मिलने वाले मुआवजे की रकम को लगभग दुगुना कर दिया था। कोर्ट की संवेदनशील पहल नीति-निर्देशनों के लिये आंख खोलने वाली सार्थक होनी चाहिए। इस दिशा में कोर्ट का सरकार को यह सुझाव कि ईंधन की खरीद को इश्योरेंस कराने से जोड़ा जाए, एक असरदार तरीका साबित हो सकता है। सही मायने में पेट्रोल पंप असल चेकपाइंट का काम करते हैं। लोग अपने वाहनों में पेट्रोल व डीजल डलवाने के लिये नियमित रूप से प्यूल स्टेशनों पर जाते हैं। वाहन डेटाबेस और इश्योरेंस रिकॉर्ड से जुड़े ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर कैमरों का प्रस्तावित इस्तेमाल भी प्रशासन में तकनीकी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यदि इस व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह सिस्टम बिना बीमे वाले तथा बिना पंजीकृत वाहनों की पहचान करके उन पर अंकुश लगा सकता है। जो मैनुअल जांच और इससे जुड़े भ्रष्टाचार को भी कम कर सकता है। वैसे इस कोशिश की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तकनीकी व्यवधान, पुराने डेटाबेस और हाल ही में रियू की गई इश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट करने में देरी से भी कानून का पालन करने वाले नागरिकों को परेशानी हो सकती है। इसके लिये जहां नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है, वहीं पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स के संगठनों को साथ लेना भी बहुत जरूरी है। इस योजना को लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से जांच करने की भी जरूरत होगी। ताकि कानून का पालन करने वाले नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। लोगों को बताना होगा कि वाहन का बीमा कराना चालक के भी हित में है। वहीं यह नागरिकों का सामाजिक दायित्व भी है क्योंकि इसका मकसद लोगों की जान बचाना है। साथ ही दुर्घटना के शिकार लोगों को समय रहते न्याय दिलाता है। देशभर में स्वयंसेवी संघों व स्थानीय निकायों की मदद से चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान इस पुनीत कार्य में मददगार हो सकते हैं।

पेट की समस्या और मोटापे से छुटकारा दिलाएगा नावासन

A man in a blue t-shirt and shorts is performing a sit-up on a grey mat. He is in the middle of the movement, with his knees bent and feet flat on the floor. His arms are extended forward, and his head is tilted back. The background is a plain, light-colored wall.

दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। हाथों को
 शरीर के बगल में सीधा रखें। अब एक गहरा
 सांस लें, और सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे
 अपने पैरों और सोने को ऊपर उठाएँ। साथ
 ही, हाथों को आगे की तरफ खींचें ताकि वहाँ
 पैरों की ओर बढ़ें। इस दौरान आपकी नज़रें
 पैरों पर होनी चाहिए, वहीं हाथ और पैर एक
 साथ में दिखाई दें। पेट की मांसपेशियों में
 खिंचाव महसूस करें और कुछ देर इस
 स्थिति में रहें। फिर धीरे-धीरे वापस पहले
 जैसी स्थिति में आ जाएँ। आयुष्य मंत्रालय ने
 दिल की कोई गंभीर बीमारी या अस्थमा से
 जूझ रहे लोगों को नौकासन न करने की
 सलाह दी है। साथ ही अगर आपको
 माग्रेन, तेज सिरदर्द या लो ब्लड प्रेशर है
 तो आप इसका अभ्यास न करें, क्योंकि
 इससे तकलीफ और बढ़ सकती है।
 गर्भावस्था के दौरान नौकासन से परहेज
 करना चाहिए, क्योंकि यह पेट पर दबाव
 डालता है।



मेघ-मेघ राशि के जातकों के लिए
आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त लाभ के संकेत हैं।

वृषभ-वृषभ राशि वालों के लिए आज
परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना
महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मतभेद को
बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल
सकता है।

मिथुन-मिथुन राशि के जातकों के लिए आज नए अवसरों का दिन है। व्यापार और नौकरी में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें।

कर्क-कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति

और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यदि किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लें।

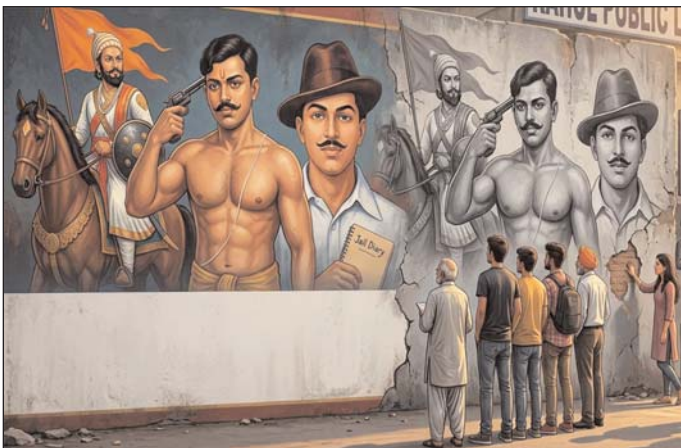
सिंह-सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और अधिकार मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है।

कन्या-कन्या राश वाला का आज परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालन की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन विवाद से बचें।

तुला-तुला राशि के लिए आज का दिन
रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। कला, साहित्य, शिक्षा और सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में

अब शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग क्यों नहीं मिलते?

आज के एक-दूसरे पर निर्भर समाज में युवाओं, खासकर जेनरेशन जेड (जेन जी) का व्यवहार समाज के लिए बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्हें अक्सर बेसब्री, बिना सोचे-समझे सोचने की आदत और कुछ मामलों में, बुरे बर्ताव वाला माना जाता है। यह सोच, हालाँकि आम हो सकती है, और हर व्यक्ति में अलग-अलग भी हो सकती है। लेकिन यह इसके अंदरूनी कारणों और समाज की संभावित प्रतिक्रियाओं की एक जरूरी जांच को बढ़ावा देती है। इन उभरते हुए पैटर्न को समझने के लिए एक बहुआयामी नज़रिए की जरूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी को तरक्की, पढ़ाई के बदलते तरीकों, पेरेंटिंग स्टायल में बदलाव और बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल के गहरे असर को माना जाए। यह आवश्यक है कि जेन जी में इन आदतों के पीछे के संभावित कारणों पर गहराई से चर्चा हो, जिसमें डिजिटल इमर्शन, तुरंत मिलने वाले फ़ायदे का असर, जानकारी लेने का बदलता तरीका और उनके विकास को आकार देने वाले बदलते सामाजिक ढाँचों पर विचार किया जाए। तदनुसार, समाज ऐसे सुधार करें जिनसे इस पीढ़ी में ज़्यादा सब्र रखने, ज़्यादा तार्किक सोच विकसित करने और सम्मानजनक बातचीत को बढ़ावा मिलें। जेन जी को बनाने वाले सबसे बड़े और असरदार कारणों में से एक है, हाइपर-कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में उनकी परवरिश। कम उम्र से ही, यह पीढ़ी, ऐसे माहौल में रही है जहाँ जानकारी, मनोरंजन और बातचीत उनकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाती है। स्मार्टफ़ोन, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और हाई-स्पीड इंटरनेट ने तुरंत मिलने वाले फ़ायदे का एक नोईसिस्टम बनाया है। अपडेट के साथ नोटिफ़िकेशन आते हैं, न्यूज़ साइकिल मिनटों में रिफ़्रेश हो जाती हैं, और मनोरंजन ऑन डिमांड उपलब्ध होता है। तुरंत फ़ीडबैक और आसानी से मिलने वाले कंटेंट की यह लगातार स्ट्रीम अनजाने में ही डेवलप हो रहे दिमाग को जल्दी नतीजे और तुरंत इनाम की उम्मीद करने के लिए ढेर कर



सकती है। इसलिए, जिन हालात में सन्न की जरूरत होती है, जैसे जवाब का ईंजाफ करना, को लंबा काम पूरा करना, या धीरे-धीरे, सोच-समझकर सोचना, वे फ्रेस्ट्रेंटिंग और अनचाही लगे सकती हैं। ऑनलाइन बातचीत का तेज नेचर, जहाँ छोटे मैसेज और थोड़ी देर का कण्टेंट ज्यादा होता है, लगातार ध्यान और गहरी बातचीत के लिए काम डॉलर्स में भी योगदान दे सकता है, जिससे बेसव्री का कल्चर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मैसेजिंग ऐप पर तुरंत जवाब की उम्मीद या सोशल मीडिया फ्रीड पर तेजी से स्कॉल करने से लोग तुरंत संतुष्टि की उम्मीद करने लगते हैं, जिससे असल दुनिया की बातचीत की भीमरी रफ्तार मुश्किल लगने लगती है। नई चीजों और तेजी से जानकारी के इस लगातार संपर्क से बोरियत की क्षमता भी कम हो सकती है, ऐग ऐसी स्थिति जो अक्सर सोचने और क्रिएटिव प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स के विकास को बढ़ावा देती है। जब डिजिटल ध्यान भटकाने वाली चीजों से बोरियत तुरंत दूर हो जाती है, तो सब्र और सेल्फ-रेगुलेशन को विकसित करने के मौक़े कम हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और लॉजिकल रीजनिंग का खतम होना डिजिटल युग ने जानकारी को डेमेक्रेटाइज कर दिया है, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिलने वाली हो गई है। लेकिन, इस एक्सेसिबिलिटी के साथ एक बड़ी चुनौती

आती हैं: उपलब्ध जानकारी की बहुत ज्यादा मात्रा और अक्सर अनवैरिफाइड नेचर। जेनरल, जो इस बहुतायत के साथ बड़ा हुआ है, अक्सर शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट, सोशल मीडिया पोइंड्स और वायरल ट्रेंड्स के जरिए जानकारी लेता है। इस्तेमाल का यह तरीका क्रिटिकल इवैल्यूएशन और लॉजिकल एनालिसिस के बजाय इमोशनल रैजोनिंग और तुल्य एंगेजमेंट को प्रायोरिटी दे सकता है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एल्गोरिदम यूजरों को एंगेज रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अक्सर ऐसा कंटेंट दिखाकर जो उनके मौजूदा बयान से मेल खाता है या मजबूत इमोशनल रिएक्शंस को कसता है। इससे इन्वीजिबल चैंबर बन सकते हैं, जहाँ लोग मुख्य रूप से उन नज़रियों के संपर्क में आते हैं जो उनके अपने नज़रियों को कन्फर्म करती हैं, जिससे अलग-अलग नज़रियों से जुड़ने और बारीक समझ डेवलप करने की उनकी क्षमता में क्वांटिटाटिव आती है। नतीजतन, थ्रोसेमंड सोर्स और गलत जानकारी के बीच अंतर करना एक मुश्किल काम बन जाता है। 'फेक न्यूज़' और 'संसेनसेशनलाइज्ड कंटेंट के फैकटर्स से युवाओं के लिए मजबूत क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, कम जानकारी के आधार पर जल्दी से राय बनाने का दबाव, जो अक्सर ऑनलाइन बहस और तेजी से की जाने वाली कमेंट्री से और बढ़ जाता है, बेतुक

परमाणु हथियारों के प्रतिबंध की वकालत करती है हिरोशिमा ग्रासदी

मानव इतिहास में '6 अगस्त 1945' की मनहूस तारीख को शायद ही कोई भूल पाए। 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में मनाई जाती है। ये तारीख। इस तारीख में सिर्फ तबानी लिखी थी। तारीख में भीसा मुकर वक्त था जिम्मे मात्र 16 मिनट के पीसर 1,30,000 लोगों की सांसें एक साथ रोकी थी। हताहतों का आंकड़ा फिलहाल सरकारी है, पर वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जाती है। हिरोशिमा पर किए परमाणु हमले में मरने वालों में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें भी थीं। सुबह करीब 8:15 बजे अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपने 'बी-29' एनाला गे। विमान द्वारा आसमान से परिमाणु बमों की बारिश करके पूरा शहर जिंदा जला दिया था। घटना के वक्त ज्यादातर लोग सोपे हुए थे, परमाणु बम ने उन्हें सोता ही मार दिया। हिरोशिमा में जब परमाणु बम फोड़ा गया, तो जापानियों को लगा कि सूरज फटा है। जबकि, वह सूरज नहीं, बल्कि तथ्याकथित विकसित, सभ्य और मुद्दी बर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर चंद मिनटों में उड़ गए। घटना का सामूहिक हत्यारा अमेरिका था। अगस्त माह की जब 6 तारीख आती है या फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती तादात पर वैश्विक मंचों पर विमर्श होता है, तो जापान



की दिल दहला देने वाली यह घटना आँखों के सामने अनायास तमूझ पड़ती हैं। घटना को श्रद्धालजिज के और ही सालाना 6 अगस्त को 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में विश्व मनाता है। यह दिन उन मुल्लकों को संकल्पित होने को आहवान भी करवाता है, जो परमाणु बम फोड़ने की अनाअवश्यक धमकी दिया करते हैं। साथ ही अहिंसा, त्रासदी, को छोड़कर भाईचारा अपनाते और शांति के पथ पर चलने को जागरूक भी करता है। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर गिराए गए अलग-अलग तारीखों पर परमाणु बम की यह कहानी जबल अध्याय के रूप में तबतक दर्ज रहेगी, जबतक दुनिया इस धरती पर बाम करेगी। 6 अगस्त को गिराए पहले बम का नाम 'एनलागे मे' था। वहीं, 9 अगस्त वाले बम का नाम 'लिटिल बॉय' यानी थूरेनियम-आधारित परमाणु बम था जापान का जबल तब अस्तित्व रहेगा, उनके लोग अमेरिका को माफ नहीं करेंगे। जापान के अलावा पूरे विश्व में इस मानव त्रासदी की निंदा प्रत्येक अगस्त को की जाती है। नागासाकी पर गिराए बम से भी लाखों की संख्या में बैकसूर नागरिक मरे थे। हिरोशिमा दिवस वैश्विक स्तरीय पर परमाणु हथियारों के विरुद्ध एकजुट होने एवं समूचे अमन-शांति की वकालत के लिए भी याद किया जाता है। साथ ही भविष्य में ऐसे विनाशकारी नुष्टों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों को बंद करने की पुरजोर अपील भी करता है। हिरोशिमा पर गिराए गए

तर्कों को अपनाने या बिना सबूत वाले दावों को मानने की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्सिपिरेसी थ्योरी की लोकप्रियता, जिनमें अक्सर अनुभव के सबूत नहीं होते लेकिन वे भावनात्मक रूप से मजबूत होती हैं, यह दिखाती है कि बिना वेरिफाई की गई जानकारी कैसे लोगों का ध्यान खींच सकता है और कर पर असर डाल सकती है। उन्हें कैसे जाना जाए, इस बारे में पूरी ग्राइडेंस के बिना विभिन्न नज़रिया के लगातार संपर्क में रहने से कम्प्यूजन हो सकता है और मिस्ट्रीमैटिक, लॉजिकल तरीकों के बजाय ब्रुटिस्टिक्स या भावनात्मक अपील पर खुद हो सकता है। 'मैनस' की परिभाषा बुरा एक जैसी नहीं है; यह सोशल नॉर्मस और टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ बदलती रहती है। जेन जी की बातचीत काफी हद तक डिजिटल कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। टेक्सिक, डायरेक्ट मैसेजिंग और ऑनलाइन कमेंट्स में अक्सर बिना बोले इशारे, आवाज का टोन और सोशल कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है जो आमने-सामने की बातचीत के लिए जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, एक साफ-साफ टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले के लिए एक अच्छी बातचीत हो सकती है, लेकिन पत्नी वाला इसे खारिज करने वाला या बदतमीजी समझ सकता है, खासकर अगर उसमें ग्रीटिंग या आखिर में बात करने जैसी आम तमीज न हो। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलने वाली गुमनामी या दूरी से हिचकिचाहट कम हो सकती है, जिससे ज्यादा गुस्सेल या बेपरवाह व्यवहार हो सकता है जो शायद सीधे, आमने-सामने की मुलाकातों में न हो। इसके अलावा, पेरेंटिंग स्ट्रैटजी में बदलाव, कुछ स्टडीज में ज्यादा डूट देने वाली पेरेंटिंग का ट्रेंड बताया गया है, अनजाने में बच्चों के लिए जरूरी सोशल दक्षता, जैसे हमदर्दी, झगड़े मुनबाजता, और अर्थॉरिटी वाले लोगों या अलग राय का सम्मान करने के मौके कम कर सकता है। जब बच्चों को नतीजों से बचाया जाता है या सही सोशल बिहेवियर के लिए लगातार

गाइड नहीं किया जाता है, तो उन्हें तभी से बातचीत के लिए जरूरी सेल्फ-डिस्प्लिने और दूसरों के लिए सोच-विचार डेवलप करने में मुश्किल हो सकती है। आज शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवत सिंह जैसे लोग क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जीजाबाई (शिवाजी की माँ) जैसी माँ नहीं हैं। एक बच्चे की अच्छी परवरिश उसे देशभक्त और भविष्य का नागरिक बनाने के लिए बुढ़ा जरूरी है। जेन जी में कहीं जल्दी अनुशासनहीनता को ठीक करने के लिए पूरे समाज को एक साथ और कई तरह के तरीके अपनाने की जरूरत है। सिर्फ बुरा करने से आगे बढ़कर ऐसे रचनात्मक दखल पर ध्यान देना जरूरी है जो सकारात्मक विकास को बढ़ावा दें। इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका डिजिटल साक्षरता और क्रिटिकल सोचने-समझने के कौशल को बढ़ाना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्टैंडर्ड्स को डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से संचालन करना सख्त को प्राथमिकता देने चाहिए। इसमें गलत जानकारी की पहचान करने, एल्गोरिदमिक बायस को समझने और ऑनलाइन सोर्स की क्रेडिबिलिटी को वैल्यूएट करने में साफ इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना सिर्फ एक एकेडमिक कोशिश नहीं है; इसके लिए अलग-अलग कॉन्टेन्ट्स में लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। डिबेट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनमें कई सोर्स से जानकारी को सिंसेसाइन करने की जरूरत होती है, और ऐसी डिस्कशन जिनमें कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमाज को एक्सप्लोर किया जाता है, ये सभी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षक खुलकर इस पर चर्चा करके क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल बना सकते हैं कि वे जानकारी को कैसे वैल्यूएट करते हैं और राय कैसे बनाते हैं। पेशेंस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत सोच-समझकर कोशिश करने के लिए होती है जो इसे बढ़ावा दे। यह घर और स्कूल दोनों जगह से शुरू हो सकता है।

सुबह करीब 8:15 बजे अमेरिका में हिरोशिमा पर अपने 'बी-29 'एनाला गे' विमान द्वारा आसमान से परमाणु बमों की बारिश करके पूरा शहर जिंदा जला दिया था। घटना के वत ज्यादातर लोग सोए हुए थे, परमाणु बम ने उन्हें सोता ही मार दिया। हिरोशिमा में जब परमाणु बम फोड़ा गया, तो जापानियों को लगा कि सूरज फटा है। जबकि, वह सूरज नहीं, बल्कि तथ्याकथित विकसित, सय और मुझी भर लोगों का निर्णय तथा एक महाशक्ति द्वारा निर्मित कृत्रिम सूरज था जिसकी आग में लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर चंद मिनटों में उड़ गए। घटना का सामूहिक हत्यारा अमेरिका था। अगस्त माह की जब 6 तारीख आती है या फिर परमाणु हथियारों की बढ़ती तादात पर वैश्विक मंचों पर विमर्श होता है, तो जापान की दिल दहला देने वाली यह घटना आँखों के सामने अनायास उमड़ पड़ती है। घटना को रूथालजि के तौर पर ही सालाना 6 अगस्त को 'हिरोशिमा दिवस' के रूप में विश्व मनाता है।

परमाणु बम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन 'डेलानो रूजवेल्ट' के सन्दर्भ में 'लिटिल बॉय' और नागासाकी के बम को विस्मटन चर्चल के सन्दर्भ में 'फैट मैन' भी कहा जाता है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। वह द्वितीय विश्वयुद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान बीसवीं सदी के सबसे क्रूर व्यक्तियों में गिने जाते रहे। यह त्रासदी उनकी ही देन थी। पाकिस्तान, अफिरका जैसे मुल्क आज भी परमाणु बमों को फोड़ने की धमकी देते हैं। इसलए हिरेशिमा दिवस उनके लिए चेतावनी के अलावा सीख जैसा है। हिरेशिमा की घटना को आज 81 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य संसार आज भी युद्ध-हिंसा में संलग्न है। युं कहें कि परमाणु

हिथियाओं के डेर पर बैठ है। हाल में अमेरिका द्वारा ईराक पर परमाणु हमले के धमकी देना, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा का घटनाएं और हिथियाओं को इकट्ठा करने के हेतु के बीच हमारे सामने यह प्रश्न खड़े होता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से क्या कुछ सबक सीख पाए या नहीं? 81 साल पहले 2,50,000 हजार लोगों को मारकर भी अमेरिका को शांति नहीं मिली? अमेरिका की दादागिरी का जवाब देने का वक्त आ चुका है इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी मुल्कों को एकजुट होना होगा। साथ ही परमाणु हिथियों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के दिशा में सभी देशों को सामूहिक पहल करने की जरूरत है।

हवाई सेवा संचालन की जमीनी जिम्मेदारी

आज के दौर में विमानन (एविएशन) उद्योग दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ एयरपोर्ट पर कुशल ग्राउंड स्टाफ की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अगर आपने अपने सपनों के कैरियर को उड़ान देनी है तो एविएशन ग्राउंड ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट आपसे लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। वह ऐसा महत्वपूर्ण पेशेवर है, जो विमान के सुरक्षित, समयबद्ध और सुचारु संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि आप सीधे विमान उड़ाने के बजाय एयरपोर्ट पर एक का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। एविएशन ग्राउंड ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट का मुख्य दायित्व विमान के उड़ान भरने से पहले और उड़ान के बाद होने वाली सभी जमीनी गतिविधियों का समन्वय करना होता है। इसके अंतर्गत यात्रियों की चेक-इन प्रक्रिया, बोर्डिंग, सामान (बैगज) की लोडिंग एवं अनलोडिंग, कार्गो प्रबंधन, विमान की सफाई, ईंधन भरवाक की व्यवस्था, सुरक्षा नियमों का पालन, रैंव संचालन, विमान को



पाकिंग बे तक सुरक्षित पहुंचाना तथा उड़ान के समय का समन्वयन जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। यह विशेषज्ञ एयरलाइन एयरपोर्ट प्रबंधन, सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी टीमों के बीच समन्वयन स्थापित करता है ताकि उड़ानें बिना किसी बाधा के संचालित हो सकें। भारत में एविएशन ग्राउंड ऑपरेशंस से संबंधित अनेक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तथा डिग्री कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उनमें प्रमुख कोर्स हैं— डिप्लोमा इन एविएशन ग्राउंड ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, बीएससी इन एविएशन, एयरलाइन इन ग्राउंड स्टाफ ऑपरेशंस, एयरलाइन एंड



एयरपोर्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में एयरपोर्ट संचालन, विमान सुरक्षा, ग्राहक सेवा, कार्गो प्रबंधन, एयरलाइन नियम, संचार कौशल तथा व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकांश डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ संस्थानों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किए जाते हैं। बीबीए अथवा बीएससी जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में भी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, प्रभावी संचार कौशल तथा व्यक्तिगत को भी महत्व दिया जाता है। कुछ संस्थान लिखित परीक्षा के आधार पर भी प्रवेश देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष तक के होते हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 वर्ष के होते हैं, जबकि बीबीए या बीएससी जैसे स्नातक कार्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के होते हैं। फीस संस्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की फीस लगभग 50,000 रुपये से

1.50 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं स्नातक कार्यक्रमों की कुल फीस लगभग 1 लाख से 5 लाख रुपये तक हो सकती है। भारत में अनेक प्रगतिष्ठ संस्थान यश प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख हैं— राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) उत्तर प्रदेश, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर एंड होस्टेस ट्रेनिंग, एयरविंस एविएशन अकादमी, एवलॉन एविएशन अकादमी, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेस चेनर्ज, बॉम्बे फ्लाइट क्लब, विभिन्न राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के एयरपोर्ट मैनेजमेंट विभाग। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडियन एक्सप्रेस, स्पाइसजेट, आकासा एयर जैसे एयरलाइंस के अतिरिक्त एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, निजी एयरपोर्ट, कार्गो कंपनियां, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां, वीआईपी लाउंज सेवाएं, लॉजिस्टिक्स कंपनियां तथा विमान सेवा प्रदाता संस्थानों में नियुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

पूरे चक्कर हो गए तब परचात आसपास की जगहों ने मां बेटी को तत्काल गंभीर रूप से लोचन में रखा। उन्होंने उदात्तर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखौर में भर्ती कराया जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां कैलाश चल रहा है बताया गया है कि दंबंग विपक्षियों की लाठी डंडों और धारदार औजारों से की गई मारपीत में गंभीर चोटें आई और वह मरणासन्न स्थिति में बनी हुई है। यह भी जानकारी मिली है कि चार दिन पूर्व वक्त विपक्षियों ने मां बेटी के साथ दाम्पत्यी घटना को अंजाम दिया था इस मामले को लेकर दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने विपक्षियों के साथ मां बेटी को भी शान्ति भंग की थाराओं में चालान कर दिया था। इसके बाद दंबंग की हौसलें बुलंद थे। इसके और उन्होंने एक बार फिर गंभीर घटना को अंजाम दिया। हालांकि जखौर पुलिस में दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 115(2), 191(2), 351(3) 352 थाराओं में मामला पंजीकृत किया है। आप है कि विपक्षियों पर प्रभावशाली कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद हैं और वह लगातार मां बेटी को मित करने की नींद सुलाने की धमकियां दे रहे हैं। परिणाम से अपने साथ किसी अनहोनी का आशंका जताई है और ऐसे पक्ष होते हैं तो उन्होंने पुलिस विभाग को इसका जिम्मेदार भी बताया है।

प्रतापगढ़। वादी निवासी मुबारकपुर पाटीहार थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ द्वारा थाना मानिकपुर पर 04 अगस्त को तहरीर दिया गया कि उसकी बहन का अमित कुमार सोनकर से प्रेम-प्रसंग था तथा वह उससे विवाह करना चाहती थी। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार करने एवं कथित रूप से अपमानजनक बातें कहने से अहत होकर 03 अगस्त को मृतका घर से निकल गई और करंटी गंगा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वादी से प्राप्त तहरीर में आधार पर थाना मानिकपुर पर अमित कुमार सोनकर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ दर्ज मुकदमा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित सोनकर पुत्र संतो सोनकर निवासी ऐमाअस्भी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम पाटीहार गिरफ्तार किया गया।